



Mahendra's

**POLITY** 

# - GH COURT (ARTICLE 214)

**MOST IMPORTANT QUESTIONS** 

BY ASHUTOSH MAHENDRAS

((•)) ●LIVE | 06:30 PM



#### **UPCOMING ONLINE BATCHES**





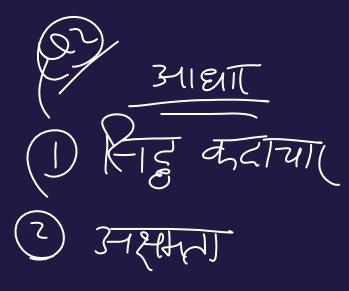






H/w Q. Who can remove the Judge of the Supreme Court?

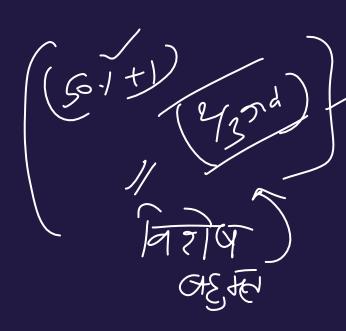
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है?



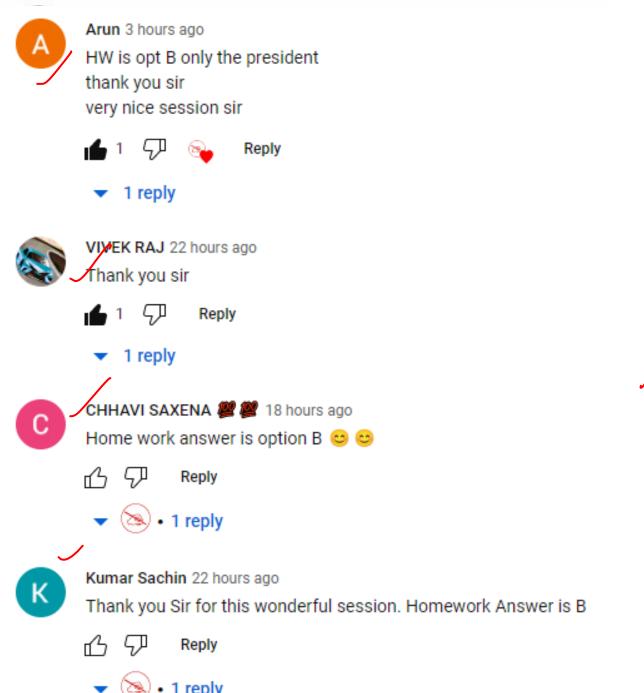
- a) Chief Justice of the Supreme Court/सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- b) Only the President/केवल राष्ट्रपति
- c) Only the Parliament/केवल संसद
- d) Both Parliament and President/संसद और राष्ट्रपति दोनों

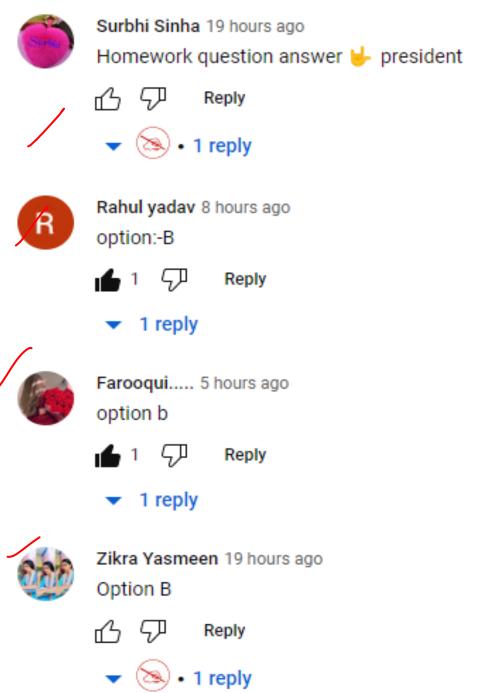


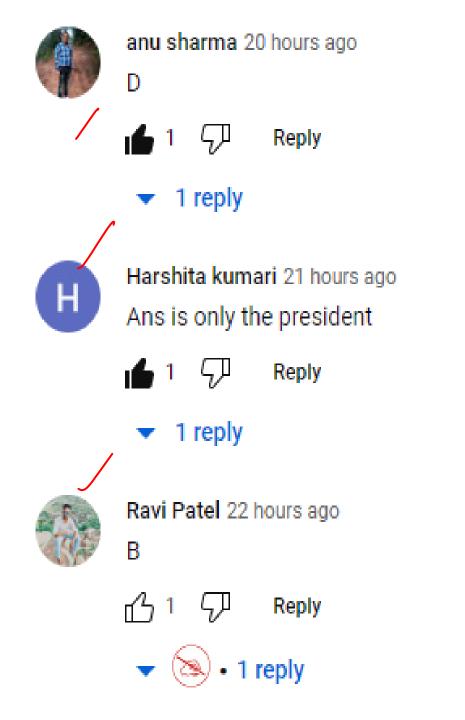


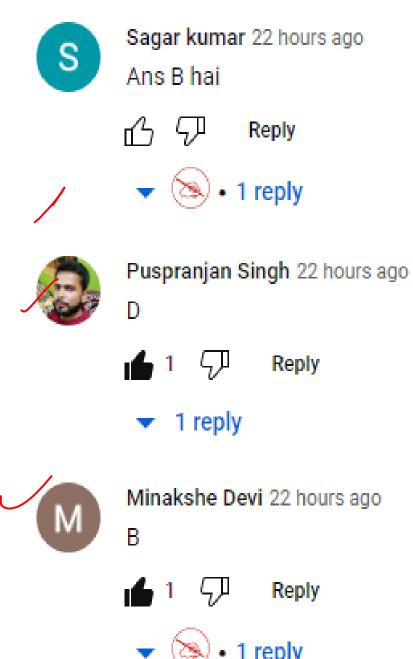


- न्य्रायाधीश को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जबकि पद से हटाने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाता है।
- The proposal for the removal of the judge should be passed with a special majority in both the Houses of Parliament, while the decision to remove from the post is taken by the President.



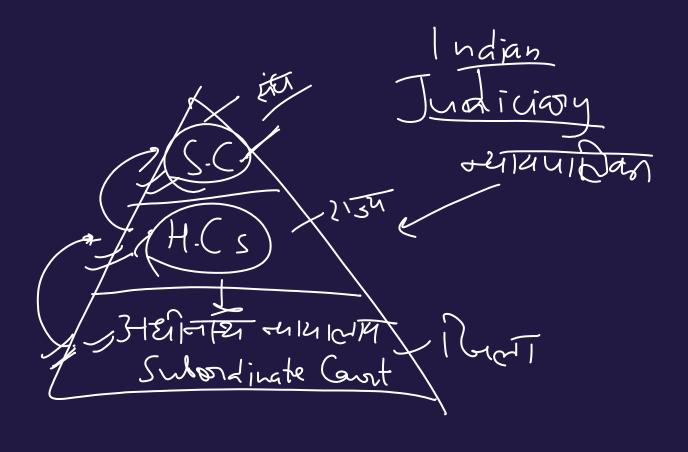














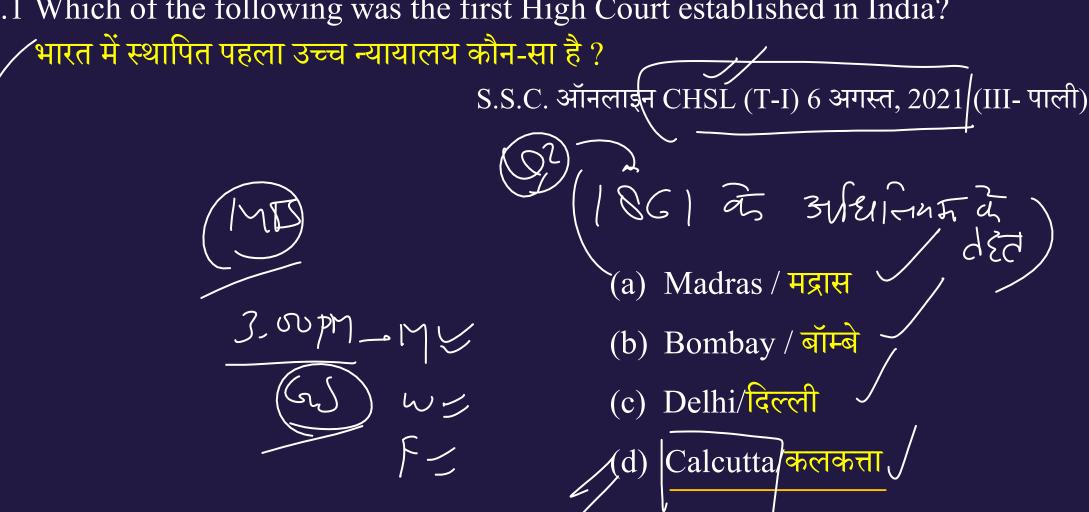


## IMPORTANT MCQs



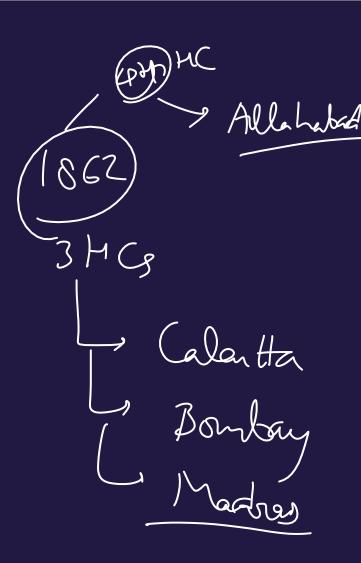


Q.1 Which of the following was the first High Court established in India?









• कलकता उच्च न्यायालय भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई, 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के अंतर्गत की गई थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तक है।

• The Calcutta High Court is the first High Court established in India. It was established on July 1, 1862 under the High Court Act, 1861. Its jurisdiction extends up to West Bengal and Andaman and Nicobar Islands.





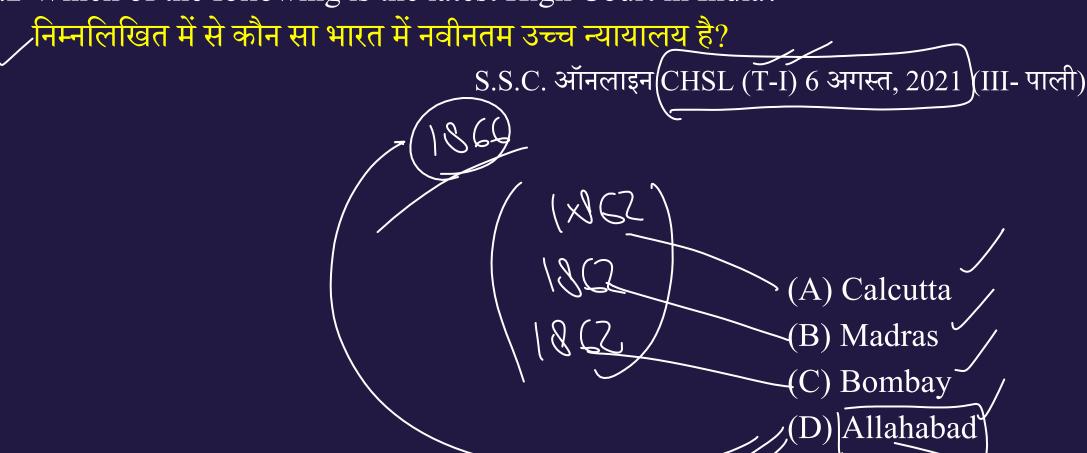
#### **List of High Courts in India**

Year	Name	Territorial Jurisdiction	Seat & Bench
862	Bombay	Maharashtra Dadra & Nagar Haveli and Daman Diu Goa	Seat: Mumbai Bench: Panaji, Aurangabad, and Nagpur
1862	Kolkata	West Bengal  Andaman & Nicobar islands	Seat: Kolkata Bench: Port Blair
1862	Madras/	Tamil Nadu Pondicherry	Seat: Chennai Bench: Madurai





Q.2 Which of the following is the latest High Court in India?







Q.3 How many High Courts are in the India currently?

भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं?

S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 6 अगस्त, 2021 (III- पाली)

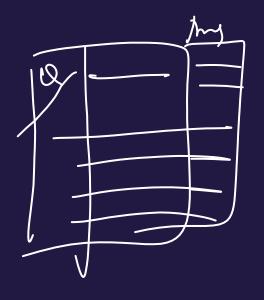
(A) 31 (B) 27 (CQ) 25 (D) 33





Q.4 Who can extend the jurisdiction of a High Court?

उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है?

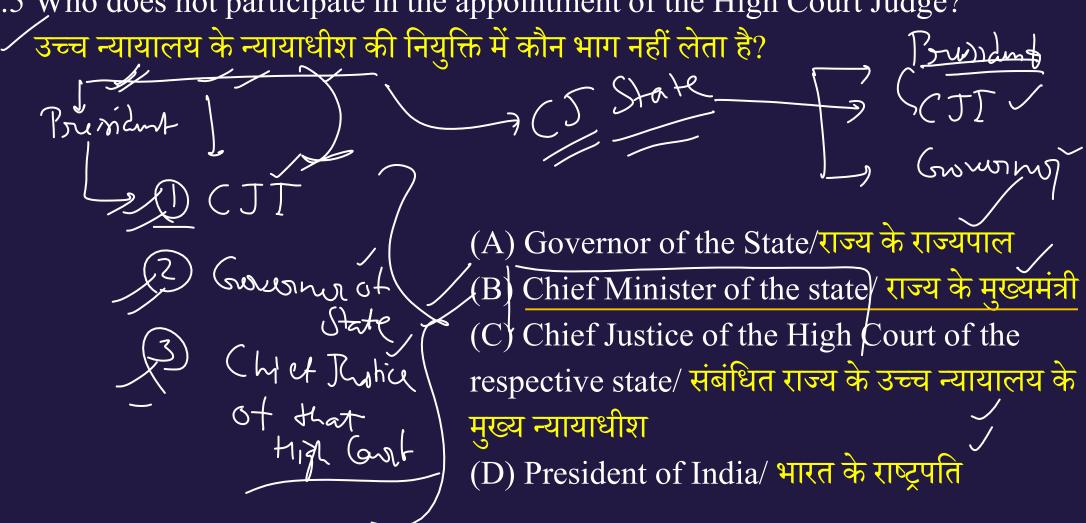


- (A) Parliament of India/भारत की संसद
  - (B) President of India/ भारत के राष्ट्रपति
  - (C) Supreme Court of India/ भारत के सर्वोच्च न्यायालय
  - (D) The governor of the state/ राज्य के राज्यपाल





Q.5 Who does not participate in the appointment of the High Court Judge?







Q.6 On which ground a High Court Judge can be impeached?

र्वितस आधार पर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है?

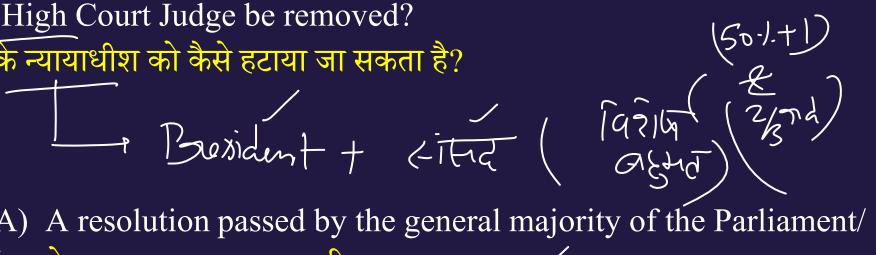
(A) Proven misconduct/सिद्ध कदाचार

(B) Incompetence/ अक्षमता
(C) Both A and B/ए और बी दोनों
(D) None of the above/ उपरोक्त में से कोई नहीं





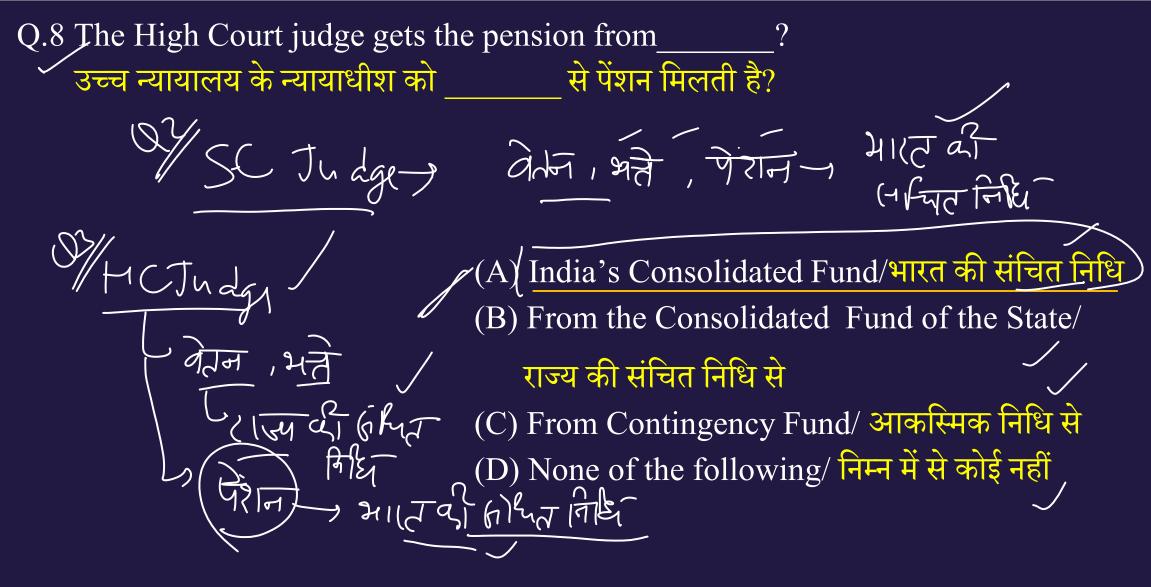
- Q.7 How can the High Court Judge be removed?
  - /उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है?



- (A) A resolution passed by the general majority of the Parliament/ संसद के सामान्य बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव 🦯
- (B) By the Supreme Court on the advice of the President/ राष्ट्रपति की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा /
- (C) A resolution passed by the special majority of the respective state/संबंधित राज्य के विशेष बहुमत द्वारा पारित एक संकल्प /
- A resolution passed by the Parliament With a special majority/ संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा











- Q.9 Which of the following state does not have a High Court?
  - निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है?

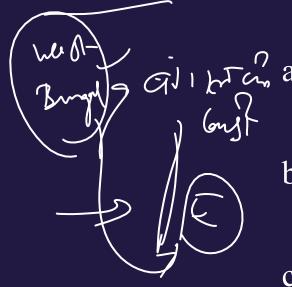
- (A) Nagaland/नगालैंड
- (B) Tripura/ त्रिपुरा
- (C) Manipur/ मणिपुर
- (D) Meghalaya/ मेघालय /





Q.10 Andaman and Nicobar islands judiciary falls under the supervision of which of the following?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायपालिका निम्नलिखित में से किसकी देखरेख में आती है?



A circuit bench of the Bombay High Court at Port आहे आहे आहे की एक सिंकट बेंच

- b) A circuit bench of the Madras High Court at Port Blair/पोर्ट ब्लेयर में मद्रास उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच
- c) A circuit bench of the Kolkata High Court at Port Blair/पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच
- d) A circuit bench of the Kerala High Court at Port Blair/पोर्ट ब्लेयर में केरल उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच





Q.11 Jurisdiction of Lakshadweep comes under \_\_\_\_\_? लक्षद्वीप का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है?

लबहाप का आवकार बन्न \_\_\_\_\_ क अतगत आता ह*?* \_\_\_\_\_\_



a) Tamil Nadu High Court/तिमलनाडु

उच्च न्यायालय

Kerala High Court/केर्ल उच्च न्यायालय

c) West Bengal High Court/पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय

d) Mumbai High Court/मुंबई उच्च न्यायालय





Q.12 The decisions of District court is subject to what kind of jurisdiction of High Court?

जिला न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के किस प्रकार के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं?

- a) Advisory Jurisdiction/ सलाहकार क्षेत्राधिकार
- b) Appellate Jurisdiction/अपील क्षेत्राधिकार
  - c) Original jurisdiction/मूल क्षेत्राधिकार
  - d) Judicial Review/न्यायिक समीक्षा





Q.13 Who was the first woman judge of the Delhi High Court?

दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थीं?

माहला न्यायाघाश कान था? S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 6 जून, 2019 (III- पाली)

- (a) Sujata Manohar / सुजाता मनोहर
- (b) Anna Chandi / अन्ना चांदी
- -(c) Lila Seth / लीला सेठ 🗸
- (d) Ruma Pal / रूमा पाल





Q.14 In which Indian state is the High Court of Lakshadweep located?

र्लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है?

S.S.C. ऑनलाइन C.P.O.S.I. (T-I) 3 जुलाई, 2017 (II- पाली)

- (a) तमिलनाडुं/ Tamil Nadu
- (b) <u>केरल/Kerala</u>
- (c) आंध्र प्रदेश/Andhra Pradesh
- (d) कर्नाटक/Karnataka







- केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत में केरल राज्य में स्थित है। क्योंकि लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है।
- The High Court of the Union Territory of Lakshadweep is located in the state of Kerala in India. Because Lakshadweep comes under the jurisdiction of Kerala High Court.





Q.15 In 1862, the High Court was first established at:

1862 में, उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहां की गई थी?

S.S.C. ऑनलाइन MTS (T-I) 18 अंक्ट्रंबर, 2021 (a) Delhi/दिल्ली (b) Jhansi / झांसी (c) Madras / मद्रास<sup>्</sup>र (d) Gwalior / ग्वालियर्







- 1862 ई. में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले मद्रास में उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत की गई थी।
- The High Court was first established in Madras in 1862 under the High Court Act, 1861.





- Q.16 Subordinate Courts are supervised by \_\_\_\_\_.
  - अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है?

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-I) 3 सितंबर, 2016 (III- पाली)

- (a) Supreme Court / उच्चत्म न्यायालय
- (b) District Court/जिला न्यायालय
- (c) High Court / उच्च न्यायालय
  - (d) Parliament संसद ।







- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण (पर्यवेक्षण) की शक्ति प्राप्त है।
- Under Article 227 of the Indian Constitution, the High Court has the power of superintendence (supervision) of all subordinate courts.





Q.17 All of the following options except one are the objectives of Lok Adalat. What is that option? \_\_\_\_\_\_

निम्नलिखित में से/एक विकल्प को छोड़कर बाकी सभी लोक अदालत के लक्ष्य हैं। वह विकल्प क्या है? S.S.C. ऑनलाइन CHSL (T-I) 8 फरवरी, 2017 () II- पाली)

- (a) कमजोर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित करना/ensuring justice to the weaker section
- (b) मामलों को बड़ी मात्रा में निपटाना/ handling large volumes of cases
- (c) आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना) handing over the power of governance to the common man
- (d) लागत और देरी को न्यूनतम करना/ minimizing cost and delay





- लोक अदालत का लक्ष्य आम आदमी के हाथों में शासन करने का अधिकार सौंपना नहीं है, जबिक कमजोर वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करना, मामलों को बड़ी (अधिक) मात्रा में निपटाना, लागत और देरी को न्यूनतम करना, महिलाओं को शीघ्र न्याय प्रदान करवाना, लोक अदालत के प्रति जनता के में जागरूकता फैलाना आदि लोक अदालत के लक्ष्य हैं।
- Lok Adalat aims at not handing over the power of governance in the hands of the common man, while ensuring justice to the weaker sections, handling large volumes of cases, minimizing costs and delays, providing speedy justice to women, To spread awareness among the public about Lok Adalat etc. are the goals of Lok Adalat.





Q.18 Lok Adalats have been created under\_\_\_\_\_.

लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं?

S.S.C. ऑनलाइन स्नातक स्तरीय (T-1) 6 जून, 2019 (I-पाली)

- (a) Legal Conciliation Act/कानूनी सुलह अधिनियम
- (b) Legal Services Authority Act / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम
- (c) Administration of Justice Act/न्याय <u>अधिनियम का प्रशासन</u>
- (d) Arbitration and Conciliation Act/पंचाट और सुलह अधिनियम





- लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन बनाई गई हैं। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा (Statutory status) दिया गया है।
- Lok Adalats have been created under the Legal Services Authorities Act. The Lok Adalats have been given statutory status under the Legal Services Authorities Act, 1987.





Q.19 The transfer of Judges from one High Court to another High Court may be made by the:

न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जा



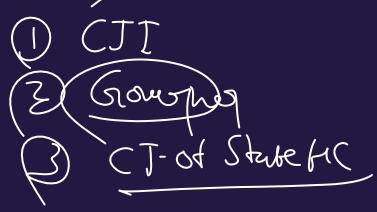
- a) President of India in consultation with the Chief Justice of that High Court./उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति
- b) Chief Justice of the concerned High Court/संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- c) Governor of the concerned State in consultation, with the Chief Justice of India./भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संबंधित राज्य के राज्यपाल
- d) President of India after consultation with the Chief Justice of India./भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद





Q.20 Under the provisions of the Constitution of India, who is entitled to be consulted by the President of India in the matter of the appointments of the Judges of the High Courts?

भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के राष्ट्रपति द्वोरा परामर्श करने का हकदार कौन है?



- a) The Union Minister of Law and Justice/केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री
- b) The Advocate General of the State/राज्य के महाधिवक्ता
- c) The Attorney-General of India/भारत के महान्यायवादी







Q.21 Under which Article(s) of the Constitution of India, is the power to issue writs for the enforcement of the Fundamental Rights vested in the Supreme Court and the High Courts?

भारत के संविधान के किस अनुच्छेद (ओं) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में निहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है?



- a) Article 32 onlyb) Article 226 only
- Article 32 and Article 226 both
- Neither Article 32 nor Article 226